



नई दिल्ली/एजेंसी। एक तरफदिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का असर दिखने लगा है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से मौसम ने फिर से पलटी मारी है। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की वजह से पारा नीचे गिर गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बीते 2 दिन से भारी बर्फबारी हो

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से 300 सड़के बंद, रास्तों में फंसे लोग

पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश और बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। अचानक से खराब मौसम हुए मौसम की वजह से चंबा, कुल्लू और किन्नौर जिले के शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां घोषित की गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भारी बर्फबारी हो रही है। शिमला में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। खबर ये भी है कि भारी बारिश-बर्फबारी और भूस्खलन के चलते चार नेशनल हाईवे समेत प्रदेश में लगभग 300 सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते 48 घंटे के दौरान भारी बारिश और तेज बर्फबारी हुई है। कई जगहों पर तो हालत ये हो गए कि कई जगहों पर तो एक फुट से ज्यादा ताजा बर्फबारी हुई है।

उत्तराखंड में भी बर्फबारी और बारिश

बदीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, पूलों की घाटी , रुद्रनाथ, लालमाटी, औली, गौरसों के साथ ही माणा में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में भी ठंड का असर बढ़ गया है। केदारनाथ धाम में भी आधा फीट तक बर्फ जम गई है। केदारनाथ धाम में दो दिनों से बर्फबारी हो रही है। तुंगनाथ, पर्यटक स्थल चोपता और कालीशीला के ऊपरी क्षेत्र के साथ ही त्रिगुनीनारायण के ऊपरी जंगलों में भी बर्फबारी हुई है।

बर्फबारी के बाद बर्फ में ढंका यमुनोत्री

गंगोत्री और यमुनोत्री में भी भारी बर्फबारी की वजह से कई फीट तक बर्फ जम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का माहौल रहेगा। टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग , पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर में भी भारी बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर के डोडा और भलेसा जिलों में भारी बर्फबारी की खबर है। पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। राजौरी जिले में भी लंबे समय तक सूखे के बाद काफी जरूरी बारिश हुई।

यूरोप के हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देना चाहता है अमेरिका

वाशिंगटन(वार्ता)। जर्मनी की दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) पार्टी सीधी रूस-अमेरिका वार्ता का स्वागत करती है लेकिन इस बात को भी महत्वपूर्ण मानती है कि वाशिंगटन यूरोप के रक्षा खर्च के साथ-साथ अमेरिकी हथियारों की खरीद भी बढ़ाना चाहता है। आरआईए नोवोस्ती ने एएफडी के सह-अध्यक्ष टियो करुपला के हवाले से यह जानकारी दी।

पाँक्सो मामले में येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ीं

बंगलूरू। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को पाँक्सो मामले में पेश होने को कहा गया है। पाँक्सो मामले की अदालत ने इस संबंध में आदेश दिया है। अमली सुनवाई पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। कोर्ट ने सह-आरोपी वाईएम अरुणा, रुदेश और मारुलासिद्धैया जी. मरिस्वामी को भी समन जारी किया है। इन सभी को उसी दिन पेश होने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने हाल ही में पूर्व सीएम येदियुरप्पा को पाँक्सो मामले में अग्रिम जमानत दी थी। बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था। मुकदमे में पहले उन्हें हाजिरी से छूट दी गई थी। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था। हाईकोर्ट ने एक नवाबालिंग से यौन उत्पीड़न के मामले में उनके खिलाफ दर्ज पाँक्सो केस को खारिज करने से मना कर दिया था और मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया था। हालांकि, इसके साथ ही कोर्ट ने येदियुरप्पा को आंशिक राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया था। जस्टिस नागप्रसन्ना ने ही पहले येदियुरप्पा को गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण दिया था।

ऑस्कर विजेता हैकमैन और पत्नी अपने आवास में मृत पाये गये

लॉस एंजिल्स(वार्ता)। दो बार के ऑस्कर विजेता जीन हैकमैन और उनकी पत्नी न्यू मैक्सिको के सांता फे में अपने घर पर मृत पाए गये। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सांता फे काउंटी शेरिफ कार्यालय ने एक बयान में कहा, हम पुष्टि करते हैं कि जीन हैकमैन और उनकी पत्नी दोनों बुधवार दोपहर को सनसेट ट्रेल पर अपने आवास पर मृत पाए गए। उन्होंने कहा कि सक्रिय जांच चल रही है, हालांकि, इस समय हमें दोनों की मौत कारण नहीं पता है। हैकमैन 95 वर्ष और उनकी पत्नी, बेट्सी अरकावा, 63 वर्ष थीं। एक स्थानीय समाचार पत्र, सांता फे न्यू मैक्सिकन ने सांता फे काउंटी शेरिफ के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत खोज वारंट हलफनामे का हवाला देते हुए बताया कि दोनों के शव उनके हाइड पार्क-क्षेत्र के घर के अलग-अलग कमरों में पंख पर पड़े पाए गए, और उनके तीन कुत्तों में से एक कुत्ता एक कोठरी में मृत पाया गया।

‘आयुष्मान भारत योजना को राजधानी में भी लागू कर रहे’

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में भी पीएम आयुष्मान भारत योजना को लागू करने जा रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने यह सबमिशन दिया। इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की मांग की, जिसकी सुप्रीम कोर्ट पीठ ने स्वीकृति दे दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार को 5 जनवरी तक दिल्ली में पीएम आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एमओयू करने का आदेश दिया था। इस पर तत्कालीन आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को अपने आदेश में उच्च न्यायालय के एमओयू करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ता ने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

■ सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका, 200 मौतों के आरोप पर कहा सबूत लाओ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से जुड़ी एक याचिका पर आज सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। दरअसल आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि मौतों का वास्तविक आंकड़ा रेलवे प्रशासन छिपा रहा है। जनहित याचिका में भगदड़ में करीब 200 लोगों की मौत का आरोप लगाया गया। याचिका में ये भी दावा किया गया कि रेलवे प्रशासन ने सिर्फ 18 मौतों की बात कही, जो गलत है। याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही रेलवे स्टेशन और



यात्रियों की मौतों की वजह आई सामने

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई 15 लोगों की मौत दम घुटने (ट्रॉमैटिक एस्फिक्सिया) की वजह से हुई। यह मौतें सीने पर जोरदार दबाव पड़ने की वजह से हुई। इसके अलावा दो लोगों की मौत हेमरेजिक शॉक की वजह से हुई, जो सीने पर तेज चोट लगने से हुआ। जबकि एक व्यक्ति की मौत सिर पर यात्रियों के भारी दबाव की वजह से हुई।

अस्पतालों के सभी सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने की मांग की। मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 200 लोगों की मौत के दावे का सबूत मांगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में अब मंगलवार को करेगा सुनवाई

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसएसआई) को संभल स्थित जामा मस्जिद परिसर की साफ सफाई करने का निर्देश दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने साफ किया है कि संभल की मस्जिद में फ्लिहाल रंगाई-पुताई नहीं की जाएगी। इस मामले में अब मंगलवार को सुनवाई होगी और इस दौरान मस्जिद कमेटी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी. बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएसआई को तीन अधिकारियों की टीम गठित कर संभल स्थित जामा मस्जिद का तत्काल निरीक्षण करने और शुक्रवार सुबह 10 बजे तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. आदालत ने कहा था, ‘रिपोर्ट में यह जानकारी दी जाएगी कि क्या परिसर के भीतर पुताई और मरम्मत की जरूरत है या नहीं. रमजान शुरू होने से पूर्व किए जाने वाले कार्य के लिए एसएसआई एक वीडियोग्राफी भी कराएगा।’

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैसे मची भगदड़?

15 फरवरी की देर रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पर उस समय भगदड़ मच गई, जब यात्रियों के बीच प्रयागराज जा रही दो ट्रेनों के रद्द होने की

अफवाह फैली। इस हादसे में 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। वहीं कई लोग घायल भी हुए थे।हादसे के बाद रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था कर प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव कम किया था। रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए थे।

महरोली पुरातत्व पार्क में नए निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में दिल्ली स्थिति महरोली पुरातत्व पार्क में किसी भी नए निर्माण और मरम्मत के काम पर रोक लगा दी है। इनमें कथित तौर पर 700 साल पुरानी आशिक अल्लह दरगाह और सूफी संत बाबा फ़ीद की चिह्नगाह भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की संख्याता वाली पीठ ने जमीर अहमद जुमलाना की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में महरोली पुरातत्व पार्क में स्थित धार्मिक ढांचों को बचाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील निधेश गुप्ता ने अपने दावे के पक्ष में पुरातत्व विभाग की स्टेट्स रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि ये धार्मिक ढांचे करीब 700 साल पुराने हैं और पुनर्निर्माण से इनकी ऐतिहासिकता प्रभावित होगी सुप्रीम कोर्ट ने एसएसआई को साइट प्लान बनाने का निर्देश दिया है ताकि अतिक्रमण न हो सके। वहीं सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटयाज ने कहा कि ‘हमें देखने दीजिए कि कौन सा ढांचा नया है और कौन सा पुराना’।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली/एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। दरअसल याचिका में गुरमीत राम रहीम को कई बार पैरोल या फरलो देने पर सवाल उठाए गए। अब इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि राम रहीम को साल 2023 में फरलो दी गई थी तो फिर उसके खिलाफ अब 2025 में याचिका दायर क्यों की गई है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर ही सवाल उठाए और कहा कि यह मामला व्यक्ति विशेष से जुड़ा है और इसमें कोई जनहित का मुद्दा नहीं है।



एसजीपीसी ने यह याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हरियाणा सरकार द्वारा डेरा प्रमुख को दी जा रही पैरोल और फरलो नियमों के ही अनुसार है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी एसजीपीसी की याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल हरियाणा सरकार ने डेरा प्रमुख हाई कोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं रखा था और उनका कहना है कि डेरा प्रमुख हत्याओं की साजिश रचने के दोषी हैं न कि हत्या करने के।

बीजेपी को 15 मार्च तक मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष

बीजेपी में जल्दी ही होगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव

नई दिल्ली। बीजेपी को जल्दी ही अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। सूत्रों के अनुसार 15 मार्च तक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा 15 मार्च से पहले होने की संभावना है। बीजेपी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम पचास प्रतिशत प्रदेशों में अध्यक्षों का चुनाव जरूरी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। उन्हीं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य भी चुने जाते हैं। फ्लिहाल 36 राज्यों में से केवल 12 में ही चुनाव पूरे हुए हैं। इसलिए कम से कम छह और राज्यों में इकाई प्रमुखों के चुनाव की



जरूरत है।

बीजेपी अगले साल विधानसभा चुनाव वाले राज्यों

तमिलनाडु, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात में प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। बिहार में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। बिहार में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ही पद पर बने रहेंगे। जानकारी के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में यूपी के जिलाध्यक्षों का चुनाव पूरा हो जाएगा। उसके बाद यूपी के बीजेपी अध्यक्ष का होगा चुनाव। एक हफ्ते या दस दिन में यूपी बीजेपी को नया

जेपी नड्डा संभाल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी

जेपी नड्डा ने 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। जनवरी 2020 में, उन्हें सर्वसम्मति से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। लोकसभा चुनाव में 2024 तक बढ़ा दिया गया था। बीजेपी अध्यक्ष होने के साथ-साथ जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।सरकार में उनके शामिल होने के बाद से पार्टी उनके उत्तराधिकारी के लिए संभावित उम्मीदवारों पर विचार कर रही है।

प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा।

संभावित नुकसान...

एमके स्टालिन ने अगले हफ्ते मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई

परिसीमन को लेकर डरे हुए क्यों हैं दक्षिण भारत के राज्य, लोस सीटें यथावत रहेगी- शाह

नई दिल्ली/एजेंसी। लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का काम अगले साल शुरू होने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि इससे तमिलनाडु और दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है। इस संभावित नुकसान को देखते हुए तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के राज्यों को आश्वासन करते हुए कहा है कि 2026 के बाद होनी वाली जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन में दक्षिण भारत के किसी भी



राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। उन्होंने साफ किया कि कम जनसंख्या के बाद भी परिसीमन में दक्षिण भारत के राज्यों में लोकसभा की सीटें भी उतर भारत के राज्यों के अनुपात में ही बढ़ाई जाएंगी।शाह के आश्वासन के बाद भी परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत का

हफ्ते मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। स्टालिन की पार्टी डीएमके को लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर मिली उसकी सफलता की वजह से लोकसभा में तमिलनाडु की सीटें कम हो जाएगी। उसे लगता है कि उत्तर भारत जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, वहां लोकसभा की सीटों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। इससे लोकसभा में तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत की आवाज कमजोर पड़ेगी। डीएमके का कहना है कि यह मामला पूरे तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले पर राजनीतिक दलों को आगे आकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए।

परिसीमन और एससी-एसटी आरक्षण

साल 2001 की जनगणना के आधार पर 2007 में पूरे हुए परिसीन के बाद लोकसभा एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बदल गई। इस समय लोकसभा में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इससे पहले लोकसभा में एससी के लिए 71 और एसटी के लिए 41 सीटें आरक्षित थीं।

परिसीमन आयोग क्या है?

परिसीमन से आशय लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया से है।परिसीमन के जरिए ही लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सीटों को आरक्षित किया जाता है। परिसीमन के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग को परिसीमन आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत में अब तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है।

■

न्यूज गैलरी

3 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देकर किया कौशल उन्नयन

2383 हायर सेकण्ड्री स्कूलों में इस वर्ष शुरु की गई व्यावसायिक शिक्षा

भोपाल/नवप्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये इस वर्ष 3 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दिलाई गई है। इस शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 2383 हायर सेकण्ड्री स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विद्यार्थियों को सुलभता से रोजगार उपलब्ध कराने के लिये व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि तेजी से ब?ती हुई विश्व की अर्थव्यवस्था में हम सभी का किस प्रकार से योगदान हो। ब?ती हुई आबादी के साथ जनता के लिये उनकी शिक्षा, कौशल तथा आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार का सृजन एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसी चुनौती का सामना करने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिये स्कूलों में नये ट्रेडों की शुरुआत की गई है। इसके लिये प्रशिक्षकों की सेवा भी ली जा रही है।

शैक्षणिक गुणवत्ता के लिये प्रशिक्षण पर जोर

प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये इस वर्ष 40 हजार से अधिक शिक्षकों को विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिलाया गया है। प्रशिक्षण की व्यवस्था में प्रारंभिक तौर पर मास्टर ट्रेनर्स भी तैयार किये गये हैं।

ड्रॉप-आउट बच्चों की संख्या कम करने के लिये प्रयास

सरकारी स्कूलों में कक्षा 5वीं से 6वीं, कक्षा 8वीं से 9वीं और कक्षा 10वीं से 11वीं में प्रवेश के समय अनेक विद्यार्थी स्कूल बदलते हैं। कुछ विद्यार्थी इस प्रक्रिया के दौरान आगामी कक्षा में प्रवेश ही नहीं ले पाते हैं। इस वजह से छात्रों के ड्रॉप-आउट की संभावना ब? जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि सभी उत्तीर्ण विद्यार्थी आगामी कक्षा में प्रवेश लें। ऐसे विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों से चर्चा कर निकटस्थ विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिये ठोस रूप से काम कर रहे हैं। विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को अपने जिले में विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट संख्या कम करने पर विशेष ध्यान देने के लिये कहा गया है।

स्वास्थ्य मानकों में मध्यप्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए कृत-संकल्पित

चिकित्सकीय समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

चिकित्सा महासंघ के प्रतिनिधियों ने पुनरीक्षित वेतनमान तथा एनपीए गणना प्रावधानों के लिये उप मुख्यमंत्री शुक्ल का व्यक्त किया आभार

भोपाल/नवप्रदेश। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने और स्वास्थ्य मानकों में मध्यप्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए कृत-संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश ने ऊर्जा, स्वच्छता, कृषि और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों के समर्पित प्रयासों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल से भोपाल स्थित निवास कार्यालय पर चिकित्सा महासंघ के



प्रतिनिधियों ने भेंट कर आभार व्यक्त किया।

चिकित्सकीय समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि चिकित्सकीय समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनकी

सुविधाओं एवं हितों की रक्षा हेतु आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि चिकित्सा कार्मिकों की सेवा संबंधी विषयों और अन्य समस्याओं के समाधान के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में

प्रयागराज से भोपाल रहे थे कार सवार

महोबा में ट्रक में घुसी कार, 4 की मौत : कानपुर-सागर हाईवे पर हादसा

भोपाल/महोबा/नवप्रदेश।

महोबा में तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे ट्रक में घुस गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। कार पूरी तरह से डैमेज हो गई। कार ट्रक में फंस गई। ट्रक 50 मीटर तक कार को घसीटते हुए ले गया। ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। एक घंटे तक चार लोग कार में तड़पते रहे। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को अलग किया। कार सवार भोपाल के रहने वाले थे।

हादसा शुक्रवार सुबह कानपुर-सागर हाईवे पर श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र में बरा स्टैंड के पास हुआ। कार सवार महाकुंभ से स्नान करके भोपाल लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।



प्रयागराज से जा रहे थे भोपाल कार सवार चारों लोग प्रयागराज से मध्य प्रदेश के भोपाल जा रहे थे।

बरा स्टैंड के पास सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रक में फंसी कार को अलग किया। कार सवार भोपाल निवासी नरेश नागर पुत्र सिद्धनाथ, पूजा नागर (23) और ड्राइवर अवधेश नागर पुत्र बाबूलाल की मौके पर मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां उपचार के दौरान महिला की भी मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

SDM सदर जितेंद्र कुमार ने बताया कि कानपुर-सागर हाईवे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार के कारण कार सीधे ट्रक के अगले हिस्से में जा घुसी। जिससे 4 लोगों की मौत हो गई है। यह सभी प्रयागराज से भोपाल जा रहे थे।

भोपाल में ऐशबाग थाने का एएसआई लाइन अटैच लगातार वसूली की शिकायतों के बाद अधिकारियों ने की कार्रवाई

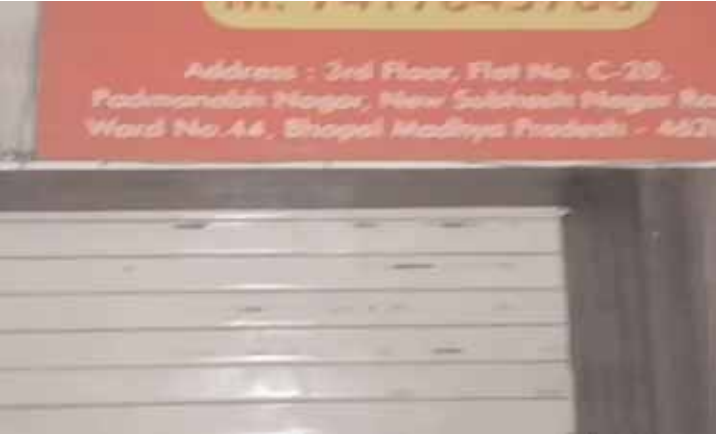
भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल के ऐशबाग थाने में पदस्थ एएसआई पवन रघुवंशी को शुक्रवार को लाइन अटैच कर दिया गया। पवन पर ठगी के कॉल सेंटर संचालक पर लचर कार्रवाई के आरोप थे। इसी के साथ पिछले दिनों उन पर जुआरियों से सांठ-गांठ के भी आरोप उन पर लगे थे। इस मामले की भी विभागीय जांच चल रही है।

इस मामले में की गई कार्रवाई

भोपाल में प्रभात चौराहा स्थित एक बिल्डिंग में संचालित ‘आइडियालॉजी एडवांस स्टैंक प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कॉल सेंटर पर पुलिस ने 23 फरवरी को छापा मार कार्रवाई की थी। गुरुवार को पुलिस ने कॉल सेंटर को पूरी तरह से सील कर दिया।

कार्रवाई एएसआई पवन रघुवंशी ने की थी। सूत्रों की माने तो पवन और टीम ने कॉल सेंटर पर जिस समय दबिश दी। तब वहां कॉल सेंटर का संचालक अफजल खान मौजूद था। वह पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। पुलिस ने उसके बेटे पर बेहद साधारण धाराओं में कार्रवाई की। जिससे आरोपी के बेटे अमान को आसानी से जमानत मिल गई।

पूरा मामला आला अधिकारियों के



संज्ञान में आने के बाद एएसआई को लाइन अटैच कर दिया गया। जबकि कॉल सेंटर में कार्यरत युवक-युवतियों ने कार्रवाई के तत्काल बाद पूछताछ में खुलासा किया कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार में निवेश से संबंधित विज्ञापन प्रसारित करते थे।=

80 से अधिक कम्प्यूटर जब्त

कॉल सेंटर से 80 से अधिक कम्प्यूटर और 26 मोबाइल सिम जब्त की गई हैं। साइबर पुलिस की मदद से ऐशबाग पुलिस कम्प्यूटर से डिलॉट डेटा रिकवर करने में जुटी है। पुलिस को कॉल सेंटर के सरगना की एक डायरी भी

मिली है, जिसमें 100 से अधिक नाम और मोबाइल नंबर दर्ज हैं। इन सभी लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है।

ठगी में इस्तेमाल हो चुकी है जल सिम

जांच में खुलासा हुआ है कि जब्त सिम कार्ड में से एक का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी के लिए किया गया था, जिसकी शिकायत लखनऊ में दर्ज लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रदेश के सभी संभागों में प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा।



समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष डॉ मनोज यादव ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि समाजवादी पार्टी, मध्य प्रदेश, 1 मार्च से 31 मार्च तक एक व्यापक सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें हर नागरिक को पार्टी से जुड़ने और सामाजिक न्याय, समानता व प्रगति की इस यात्रा का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। यह अभियान प्रदेशभर में समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने और जनता की आवाज़ को सत्ता के केंद्र तक पहुंचने का एक सुनहरा अवसर है। मनोज यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन को सफलतापूर्वक लागू करने का दावा तो किया, लेकिन क्या उसने इसके संभावित दुष्प्रभावों पर सही

कॉल सेंटर का संचालक अफजल खान, उसकी बेटी सायमा और परिवार के अन्य सदस्य ग्रीन पार्क कॉलोनी, अशोका गार्डन स्थित घर में ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। पुलिस को अफजल के टीकमगढ़ का निवासी होने की जानकारी मिली है। हालांकि, अब तक आरोपियों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।

जांच में यह भी सामने आया है कि अफजल खान के बैंक खाते का इस्तेमाल कई साइबर ठगी की रकम के ट्रांजैक्शन में किया गया है। पुलिस को इस संबंध में पुख्ता प्रमाण मिले हैं। महाराष्ट्र में हुई एक साइबर ठगी की रकम अफजल के खाते में ट्रांसफर हुई थी। पुलिस ने केस के फरियादी से संपर्क कर लिया है। उसके भोपाल पहुंचने पर एफआईआर दर्ज करने के दावे किए जा रहे हैं।

लगातार सुर्खियों में है ऐशबाग थाना

इधर, ऐशबाग थाने के पुलिस जवानों पर जुआरी को संरक्षण देने के आरोप सही निकले हैं। मंगलवार को एसीपी सुरभि मीणा ने आला अधिकारियों को सौंपी प्राथमिकी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि कर दी है। यह जवान जुआरी से लंबे समय से संपर्क में थे

एनडीपीएस की फर्जी कार्रवाई के आरोप लगे थे

बता दें ऐशबाग पुलिस ने फरहान खान को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। यह वही फरहान है जो क्षेत्र में लंबे समय तक जुआ खिलवाता रहा है। इसके बाद फरहान के साले ने जहर खा लिया था। फरहान की पत्नी ने वीडियो वायरल कर पुलिस जवानों के संरक्षण में जुआ खिलाने के आरोप लगाए थे। फरहान की पत्नी ने जुआ की बंदी समय पर नहीं देने से नाराज होकर पुलिस द्वारा एनडीपीएस की कार्रवाई की जाने के आरोप लगाए थे।

एंबुलेंस में डिलीवरी, परिजन से धुलवाई गाड़ी



मैहर में मां-नवजात अस्पताल में भर्ती; वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर-अटेंडर को हटाया

मैहर/नवप्रदेश। मैहर जिले में अमानवीय घटना सामने आई है, जहां एक एंबुलेंस ड्राइवर ने मानवता को शर्मसार कर दिया। जिले के अमरपाटन सिविल अस्पताल में भर्ती होने पहुंची प्रसूता के परिजनों को ही एंबुलेंस साफ करने को मजबूर कर दिया गया।

घटना अमरपाटन ब्लॉक के पमरा गांव की है। गुरुवार दोपहर गर्भवती ममता कोल को 108 एंबुलेंस (छब 04 हैं 1305) ने अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी

डिलीवरी हो गई। अस्पताल पहुंचने पर मां और नवजात को भर्ती कर लिया गया।इसके बाद एंबुलेंस ड्राइवर ने प्रसूता के परिजनों से वाहन की सफाई करवाई। वे नल से पानी भरकर एंबुलेंस धोने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो गया।

सरकार ने अनुबंधित संस्था को नोटिस किया जारी

सीएमएचओ डॉ. एलंके तिवारी ने कहा कि एंबुलेंस की सफाई को जिम्मेदारी ड्राइवर और स्टाफ की होती है। प्राथमिक जांच के एम्बुलेंस ड्राइवर और अटेंडर को पद से हटा दिया गया है। उन्होंने राज्य शासन स्तर से अनुबंधित संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उद्घोषणा	
नव प्रदेश, जबलपुर	
रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर्स (सेन्ट्रल रूल्स 1956 के अंतर्गत) दैनिक नवप्रदेश पत्र के संबंध में स्वामित्व तथा अन्य विवरण विषयक-जानकारी	
घोषणा पत्र फार्म-4	
1. प्रकाशन स्थल-	402, कौशलया विहार, नेमियर टाउन जबलपुर, 482001
2. प्रकाशन अवधि-	दैनिक
3. मुद्रक का नाम- नागरिकता- पता-	यशवंत धोटे भारतीय 3/ए, /21-सेक्टर 8 भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
4. प्रकाशक का नाम- नागरिकता- पता-	यशवंत धोटे भारतीय 3/ए, /21-सेक्टर 8 भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
5. संपादक का नाम- नागरिकता- पता-	सुशील दत्त भारतीय 881/ए बाई का बगीचा, शीतला माई बाई, गली नंबर-3 घमापुर, जबलपुर, 482001
6. उन व्यक्तियों का नाम- व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हैं।	यशवंत धोटे भारतीय 3/ए, /21-सेक्टर 8 भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
मैं यशवंत धोटे एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।	
जबलपुर दिनांक 1 मार्च 2025	
यशवंत धोटे प्रकाशक के हस्ताक्षर	



आज से माशिमं बोर्ड परीक्षाएं शुरु

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में आज से प्रवेश शुरु, गाइडलाइन जारी

बिलासपुर/नवप्रदेश। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने के लिए एक मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरु हो रही है। लोक शिक्षण संचालय ने स्कूलों को 28 फरवरी तक सीटों की संख्या को पोर्टल में अपडेट करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। शहर में वर्तमान में 537 निजी स्कूल हैं, जिसमें से लगभग 300 स्कूलों ने ही आरटीई के लिए पंजीयन करवाया है। इसके साथ ही जिन स्कूलों ने पंजीयन नहीं करवाया है उनका आरटीई में पोर्टल नहीं खुलेगा। आरटीई के तहत तीन से साढ़े 6 साल तक के बच्चे किसी भी निजी स्कूलों में शुरुआती कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं।



इसके लिए शासन द्वारा कुछ जरूरी दस्तावेज तय किए हैं। उन दस्तावेजों के आधार पर बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की

सुविधा है। आरओई के लिए कक्षा नर्सरी के लिए बच्चों की उम्र 3 से 4 वर्ष होना जरूरी है। प्रभारी शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कोई भी स्कूल शिक्षा के अधिकार के

आरटीई के लिए ये दस्तावेज है जरूरी

आरटीई के तहत आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। बीपीएल सर्वे सूची में नाम, सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना सर्वे सूची 2011 पंजीयन क्रमांक अंत्योदय कार्ड, असुविधा राहत वर्ग एससी (अनुसूचित जाति), एसटी (अनुसूचित जनजाति), दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र) , आदिम आदिवासी समूह (तहसीलदार द्वारा सत्यापित स्थायी जाति प्रमाण पत्र) , वन निवासी अनुसूचित जाति (वन पट्टा) , एचआईवी (सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र), अनाथ (बाल कल्याण समिति द्वारा जारी सूची में नाम) इनमें से किसी एक दस्तावेज की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही माता-पिता एवं बच्चे का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, दुर्बल वर्ग या असुविधा वर्ग में से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य है।

तहत प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होते ही उन्हें आरटीई की प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है। अल्पसंख्यक स्कूल को ही आरटीई के

तहत प्रवेश नहीं लेने की छूट होती है। बाकी सभी स्कूलों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। शिकायत आने पर जरूरी कार्रवाई की जाती है।

दसवीं व बारहवीं की परीक्षाएं आज से

माशिमं की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं आज से शुरु हो रही हैं। प्रभारी शिक्षा अधिकारी पी. दासस्थी ने बताया कि जिले में 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं में लगभग 42 हजार 116 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है और प्रश्न पत्रों का वितरण कर दिया गया है। सभी प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों के नजदीक थानों में सुरक्षित रखे गए हैं। नकल लेकने के लिए प्लाइगन स्वर्चोंयड की 6 टीमें बनाई गई है इनमें 34 सदस्य शामिल हैं। ये टीमें परीक्षा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे। सुबह 8 बजे कलेक्टर कार्यालय के सामने जिला शिक्षा विभाग में उपस्थिति देकर केंद्रों के लिए रवाना होंगे। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी प्लाइगन स्वर्चोंयड की स्थायी तैनाती नहीं होगी।

न्यूज गैलरी

हाइवा की टक्कर से सुपरवाइजर की मौत

पचपेड़ी थाना क्षेत्र का मामला

मस्तूरी/पचपेड़ी/नवप्रदेश। थाना क्षेत्र में एनिकेट निर्माण में लगे हाइवा की चपेट में आकर एक साइड सुपरवाइजर की मौत हो गई है वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमलडीहा और ग्राम उडईबंद के बीच में शिवनाथ नदी में एनिकेट का निर्माण शुरु होना है जिसमें पहले मिट्टी की पटाई करके रैम्प बनाया जा रहा है। जिसमें गुरुवार शाम 5 बजे के आसपास निर्माण कार्य में लगे मिट्टी से भरे हाइवा क्र. सीजी 15डीयू ने पीछे करते वक्त पीछे से हाइवा को साइड दिखा रहे साइड सुपरवाइजर शैलेन्द्र चौरसिया महाराजगंज उत्तरप्रदेश निवासी को अपनी चपेट में ले लिया जिससे शैलेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई। वही हाइवा चालक घटना के बाद हाइवा को घटनास्थल में ही छोड़ मौके से फरार हो गया। जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने पचपेड़ी थाना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज आगे की जांच कार्यवाही में जुट गई है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई

अदालत तकनीकी अनुबंध मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें: हाईकोर्ट

बिलासपुर/नवप्रदेश। ठेका विवाद को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में ठेका देने में राज्य सरकार के विवेकाधिकार को बरकरार रखा है। डिवीजन बेंच ने निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि न्यायिक समीक्षा को प्रशासनिक निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वे मनमाने, अनुचित या दुर्भावना से प्रसिक्त ना हों। सीएसआईडीसी द्वारा जारी निविदा को चुनौती देते हुए आधा दर्जन से अधिक रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए जारी निविदा की प्रक्रिया को चुनौती



हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

रिट याचिका की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि एक बोलीदाता निविदा की शर्तों को पूरा करता है या नहीं, इसका संतोष मुख्य रूप से बोली आमंत्रित करने वाली संस्था पर निर्भर करता है। किसी बोलीदाता द्वारा निविदा की शर्तों को पूरा करना प्राथमिक रूप से बोली आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर करता है। ऐसा प्राधिकारी निविदादाताओं से अपेक्षाओं के बारे में जानता है, तथा गैर-निष्पादन के परिणामों का मूल्यांकन करता है।

दी गई थी। मेसर्स श्रद्धा कंस्ट्रक्शन कंपनी बोलियों को खारिज किए जाने का विरोध किया, जिसमें मेसर्स आनंदी बिल्डर्स के

पक्ष में मनमाने ढंग से निविदा जारी करने का आरोप लगाया था। निविदा प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम औद्योगिक (सीएसआईडीसी) ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से डिवीजन बेंच के समक्ष पेश जवाब में बताया कि याचिकाकर्ताओं ने निविदा की शर्तों के अलावा तकनीकी आवश्यकताओं सहित अन्य मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं। डिवीजन बेंच ने कहा कि सरकारी अनुबंधों में निष्पक्षता, समानता और कानून के शासन को कायम रखा जाना चाहिए, लेकिन निविदा प्राधिकरण के पास वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर पात्रता निर्धारित करने का विवेकाधिकार है। रिट याचिकाओं की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि न्यायालय ने पाया कि बोलियों को अस्वीकार करना वैध और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित था।

कोल साइडिंग में काम कर रहे मजदूर की करंट से मौत

बिलासपुर/नवप्रदेश। जयराम नगर कोल साइडिंग में काम कर रहे श्रमिक आर्यन उस वक्त गंभीर रूप से झुलस गया जब बिना किसी सूचना के ओवर्चार्ज (ओवरहेड इलेक्ट्रिक) लाइन को चालू कर दिया गया। यह घटना इंद्रमणि प्राइवेट लिमिटेड के कोयला लोडिंग रैक पर हुई, जहां आर्यन लोडिंग के बाद ट्रट-फूट की जांच कर रहा था। रेलवे अधिकारियों और ठेकेदारों की घोर लापरवाही के कारण हाई वोल्टेज करंट ने उसकी जिंदगी को संकट में डाल दिया।



रेलवे प्रशासन को जवाबदेह बनाना जरूरी

इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। हर कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों की जांच, श्रमिकों को समय-समय पर सतर्कता प्रशिक्षण, और सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता है। सरकार और रेलवे मंत्रालय को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। मजदूर देश की रीढ़ होते हैं, और उनकी सुरक्षा की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। रेलवे की लापरवाही ने एक और गरीब श्रमिक को मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया है।

के कारण मजदूरों की जान जोखिम में पड़ी हो। पहले भी कई बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर श्रमिकों की जिंदगी को खतरे में डाला गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या रेलवे प्रशासन इस तरह की घटनाओं से सबक लेगा या फिर भविष्य में

और मजदूरों की जान पर बन आएगी हादसे के बाद रेलवे और ठेकेदारों की चुप्पी इस बात का सबूत है कि वे अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। रेलवे सुरक्षा मानकों का पालन करने का दावा तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है।

15 दिवसीय फाइलेरिया मुक्त अभियान शुरु

बिलासपुर/नवप्रदेश। जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने के उद्देश्य से 27 फरवरी से 13 मार्च तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सिम्स संस्थान में बुध लगाकर लोगों को दवा वितरित की जा रही है जिस अनुक्रम में कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के प्रमुख अधिष्ठाता डॉक्टर रमनेश मूर्ति द्वारा दवा का सेवन कर किया गया तथा सिम्स चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह को अधिष्ठाता द्वारा दवा खिलाई गई एवं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को इस बीमारी से बचाने की सुझाव दिए गए।

लखमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 13 मार्च को अगली सुनवाई

बिलासपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। उनकी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को तय की है। इस दौरान कोर्ट ने एसीबी और ईओडब्ल्यू (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जांच एजेंसियों को आरोप है कि लखमा शराब घोटाले में शामिल एक बड़े सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। उन पर राज्य की शराब नीति बदलने



और एफएल-10 लाइसेंस शुरु करने में अलग भूमिका निभाने का आरोप है। इस लाइसेंस के चलते घोटाले को बढ़ावा मिला। ईडी ने अदालत में कहा कि लखमा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। लखमा के वकील ने अदालत में दलील दी कि

ईओडब्ल्यू ने एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारी की है, जबकि वे विधायक हैं। विधायक होने के नाते गिरफ्तारी से पहले सरकारी अनुमति जरूरी थी, लेकिन बिना अनुमति के कार्रवाई की गई। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। इससे पहले, ईओडब्ल्यू कोर्ट ने भी लखमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही, उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। अब लखमा 18 फरवरी तक जेल में

रहेगे। इस मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। कवासी लखमा फिलहाल कोटा विधानसभा सीट से विधायक हैं। शराब घोटाले में उनकी भूमिका की जांच जारी है। ईडी का कहना है कि लखमा ने राज्य की शराब नीति में बदलाव करके करोड़ों रुपये का घोटाला किया। इस मामले में कई अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब सभी की नजरें 13 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब हाईकोर्ट इस मामले में अपना अगला फैसला सुनाएगा।

भूत-प्रेत, जादू, टोना की शंका में मारपीट, 4 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर/ नवप्रदेश। भूत-प्रेत, जादू, टोना के शंका में युवक से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपियों से कोरा व बांस की छड़ी जब्त किया गया है।

पुलिस के अनुसार थाना मस्तूरी के मार्ग क्रमांक 20/2025 धारा 194 बीएनएसएस की जांच में गवाहन विस्तृत कथन किया जिसमें मृतक सरोज खाण्डेकर पिता गोरेलाल खाण्डेकर उम्र 35 साल निवासी देवागव मस्तूरी का 12 फरवरी को पंचायत चुनाव में सरपंच एवं पंच उम्मीदारी से देवागंव के लोगों द्वारा ग्राम विकास

आरोपियों से कोरा व बांस की छड़ी जब्त



के नाम पर कुछ सामानों की मांग किये एवं पार्टी मानने हेतु उम्मीदगरो से चिकन पार्टी के लिए बोले जो ग्राम सरपंच के उम्मीदगरो द्वारा चिकन पार्टी व दारू के लिए पैसा दिये जिसमें गाव के

अन्य लोगो एवं मृतक सरोज खाण्डेकर के अपने घर में चिकन पाटी का आयोजन किया गया जो कि मृतक सरोज खाण्डेकर 12 फरवरी को सुबह से शराब का सेवन करना उसके दोस्त के द्वारा बताया गया जो घटना दिनांक अत्यधिक शराब का सेवन करने से तबीयत खराब होकर जमीन में सिर के बल गिर पड़े मौके पर उसका छोटा भाई शैलेन्द्र एवं मुकेश खाण्डेकर भी चिकन पार्टी में शामिल था जो शैलेन्द्र एवं मुकेश अपने भाई को जमीन में सिर

के बल गिरे होने पर भूत प्रेत चढ़ने की बात बोलकर अपने बड़े भाई मनोज खाण्डेकर एवं पिता गोरे लाल खाण्डेकर को झाड फूंक के लिए बुलाना जो भोके पर मनोज खाण्डेकर एवं गोरे लाल खाण्डेकर आकर मृतक सरोज खाण्डेकर को झाड फूंक के नाम पर मा बहन की गाली गलौज करते हुए हाथ में कोर्स से मारपीट किये जो विडियो वायरल में साफ-साफ दिखाई दे रहा है जो जाच में मृतक सरोज खाण्डेकर को उसके भाई मनोज शैलेन्द्र खाण्डेकर मुकेश खाण्डेकर तथा पिता गोरेलाल खाण्डेकर के द्वारा भूत प्रेत जादू टोना होने की बात बोलकर मृतक के साथ मारपीट करना पाया गया।

अग्रवाल संगठन व नया सेवेरा फाउंडेशन ने बच्चों के साथ मनाया महाशिवरात्रि पर्व



बिलासपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन एवं पायल एक नया सेवेरा वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल के बच्चों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को इस पर्व के महत्व और इसके पीछे की कथा के बारे में बताया गया।

कार्यक्रम में बच्चों को प्रशाद की खीर, लीची जूस और चॉकलेट्स वितरित किए गए। बच्चे बहुत खुश और उत्साहित थे। कार्यक्रम में पायल एक नया सेवेरा की अध्यक्ष पायल लाट, सचिव चंचल सलूजा, भारती सालुंके, कृति सालुंके एवं छत्तीसगढ़ प्रांतीय से उपाध्यक्ष अनिता गणेश अग्रवाल उपस्थित रहे।

बिलासपुर/नवप्रदेश।

महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर नगर पंचायत मल्हार में 15 दिवसीय मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस आयोजन में नगरवासियों और बाहर से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में नगर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना एक बड़ी चुनौती है। इसी जिम्मेदारी को समझते हुए नगर पंचायत की अध्यक्ष धनेश्वरी धनेश्वर केवर्त ने अपने पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सफाई आशुतोष वर्मा, मनराखन केवर्त, गिथुन यादव पूर्व पार्षद शमशेर सिंह, रावि केवर्त पूर्व मंडल महामंत्री



देखा, तो बिना किसी झिझक के वे खुद मैदान में उतर गईं और सफाई कार्य में जुट गईं। उनके साथ पार्षद सुशील राजा चौबे, कमलेश सिंह, आशुतोष वर्मा, मनराखन केवर्त, गिथुन यादव पूर्व पार्षद शमशेर सिंह, रावि केवर्त पूर्व मंडल महामंत्री

सड़क पर जलभराव की समस्या से राहत मिली और श्रद्धालुओं को सुगमता से आना-जाना संभव हुआ। अध्यक्ष धनेश्वरी केवर्त और उनके साथियों की यह पहल नगरवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। आमतौर पर सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारियों पर निर्भर रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी जब खुद मैदान में उतरकर सफाई करते हैं, तो इससे जनता को भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता मिलती है। नगर पंचायत के इस प्रयास से न केवल मेला परिसर स्वच्छ हुआ, बल्कि लोगों के मन में अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति

मल्हार स्वच्छ, सुंदर और आदर्श बनकर उभरेगा

नगर पंचायत मल्हार के इस कदम से यह साबित हो गया है कि जब नेता खुद आगे बढ़कर काम करते हैं, तो बदलाव अवश्य आता है। महाशिवरात्रि मेले के दौरान नगर पंचायत ने जिस तरह से सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी, उससे यह उम्मीद जगती है कि आने वाले दिनों में मल्हार एक स्वच्छ, सुंदर और आदर्श नगर बनकर उभरेगा। इस तरह की घटनाएं न केवल अन्य नगर पंचायतों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन सकती हैं, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ऊर्जा और दिशा दे सकती हैं।



न्यूज गैलरी

कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25 फीसदी ब्याज दर बरकरार



नई दिल्ली। इससे पहले फरवरी 2024 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को मामूली रूप से बढ़ाकर 8.25 फीसदी कर दिया था। 2022-23 में यह ब्याज दर 8.15 फीसदी थी। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया गया कि सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ ने शुक्रवार को 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25 फीसदी की ब्याज दर बरकरार रखने का फैसला किया है। फरवरी 2024 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को मामूली रूप से बढ़ाकर 8.25 फीसदी कर दिया था। 2022-23 में यह ब्याज दर 8.15 फीसदी थी। ऐसे ही मार्च 2022 में ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए अपने सात करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए ईपीएफ पर ब्याज को घटाकर चार दशक से अधिक के निचले स्तर 8.1 फीसदी कर दिया था। 2020-21 में यह ब्याज दर 8.5 प्रतिशत थी। इससे पहले 2020-21 के लिए ईपीएफ पर 8.10 प्रतिशत ब्याज दर 1977-78 के बाद से सबसे कम थी। उस वक़्त ईपीएफ ब्याज दर आठ प्रतिशत थी। ईपीएफओ से जुड़े एक सूत्र ने कहा, “ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने शुक्रवार को अपनी बैठक में 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है।” सीबीटी ने मार्च 2021 में 2020-21 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर तय की थी। सीबीटी के निर्णय के बाद 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। सरकार के अनुमोदन के बाद, 2024-25 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ के सात करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी। ईपीएफओ वित्त मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद ही ब्याज दर प्रदान करता है।

यूट्यूब करने जा रहा बड़े बदलाव, अब वीडियो पर नहीं आएगी ऐड



नई दिल्ली। यूट्यूब अब ऐड्स दिखाने की पॉलिसी को बदलने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार ये बदलाव 12 मई से होने जा रहे हैं। जिसके बाद यूट्यूब पर वीडियो स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर हो जाएगा। वीडियो में डायलॉग या सीन के बीच में ऐड्स नहीं आएंगे। यूट्यूब के मुताबिक, जल्द ही यूजर्स को ऐड्स की परेशानी कम लगेगी।

मई से नैचुरल ब्रेकप्वाइंट पर ही ऐड्स नजर आएंगे। इसे आप ऐसे समझें- जैसे अभी तक आप कोई भी वीडियो देखते थे तो बीच में कभी भी और कहीं भी ऐड्स आने लगती हैं। लेकिन कंपनी इसे बदल रही है। यूट्यूब अब किसी सीन या डायलॉग के बीच ऐड्स नहीं दिखाएगा। इन ऐड्स को किसी सीन के ट्रांजिशन या पॉज पर प्लेस कर दिया जाएगा। यूट्यूब ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वीडियो के दौरान आने वाली ऐड्स से यूजर्स का मजा खराब होता था। जिसकी वजह से यूट्यूब पर वीडियो स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस खराब हो रहा था। कंपनी की पोस्ट के मुताबिक, इस बदलाव से वीडियो पर व्यूज ज्यादा आएंगे। जिसकी वजह से क्रिएटर्स की कमाई बढ़ जाएगी। यूट्यूब का बदला हुआ फीचर मई से पुराने वीडियोज पर शुरू किया जाएगा। कंपनी पुराने वीडियो पर भी मिड-रोल ऐड्स को एडजस्ट करने वाली है। ऐसे में जो क्रिएटर्स ऐड्स की प्लेसमेंट पर अपना कंट्रोल चाहते हैं वो यूट्यूब स्टूडियो में जाकर कर सेटिंग कर सकते हैं। उन्हें 12 मई से पहले इसे ऑफ-आउट करना

कारोबार

बिजनेस और टेक्नोलॉजी से तय होगा नया वर्ल्ड ऑर्डर

भारत को निभानी होगी अहम भूमिका : वित्त मंत्री

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भारत को 'ग्लोबल रीसेट' में अहम भूमिका अदा करनी होगी, क्योंकि नया वर्ल्ड ऑर्डर किसी भी विकसित देश द्वारा नहीं निर्धारित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी में एक मीडिया इवेंट में वित्त मंत्री ने कहा, विकसित देशों के पास निवेश के लिए पैसा है, लेकिन वह भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। बिजनेस और टेक्नोलॉजी नए वर्ल्ड ऑर्डर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारत को इसमें भाग लेने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को ग्लोबल रीसेट में सार्थक योगदान देने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में ऊपर बढ़ने और वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने वाला एक व्यावसायिक गंतव्य बनने की दिशा में निरंतर प्रयास करना



होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि टेक्नोलॉजी की प्रगति के मामले में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। हम टेक्नोलॉजी के कई पहलुओं में अग्रणी हो सकते हैं। हमने दुनिया को साबित कर दिया है कि जहां भी टेक्नोलॉजी की तैनाती का सवाल है, हम इसे बड़े पैमाने पर

अर्थव्यवस्था भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बना सकता है

भारत की रिटेल मार्केट 2034 तक 190 लाख करोड़ रुपये की होगी : रिपोर्ट



मुंबई। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बना सकता है। इसके साथ ही देश की खपत में भी इजाफा होगा और यह 2034 तक बढ़कर 190 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में खपत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यह इस क्षेत्र की मजबूती और गति को दर्शाता है। बीते एक दशक में भारत का रिटेल मार्केट 35 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपये का हो गया है, जो सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की गति को दिखाता है। बीसीजी के प्रबंध निदेशक और सीनियर पार्टनर, अभीक सिंघी ने कहा

कि अगले दशक में इसके 200 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है और यह सभी को अच्छे अवसर प्रदान करेगा। 2035 तक कई ट्रिलियन रुपये टर्नओवर वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए कई अवसर हैं।अनुमान है कि

कभी-कभी तीव्र अस्थिरता के दौर के बावजूद सेक्टर की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। संगठित खुदरा क्षेत्र लगातार बाजार में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। महिलाओं की भागीदारी बीते पांच वर्षों में दोगुनी हुई है और पुरुषों एवं महिलाओं में अंतर कम हुआ है। इससे महिला केंद्रित कैटेगरी जैसे ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन में वृद्धि देखी गई है।रिपोर्ट में कहा गया कि जेन जेड और मिलेनियल्स बड़े उपभोक्ता समूह हैं, जिसके कारण उनकी वैल्यू और डिजिटल-फर्स्ट आदतों के साथ तालमेल बिठाना जरूरी हो जाता है। इस बीच अगले दशक में 45 प्लस आयु वर्ग सबसे बड़ा समूह बन जाएगा, जिससे उपभोक्ता स्वास्थ्य सहित कई नए ट्रेंड उभरेगें।रिपोर्ट में बताया गया कि ऑनलाइन शॉपिंग की पहुंच 50 प्रतिशत तक पहुंचने के बावजूद 58 प्रतिशत लोग खरीदारी के लिए पूरी तरह से ऑफलाइन तरीके पर निर्भर हैं।

सुमन कुमार बने इंडियन ऑयल के निदेशक

नई दिल्ली/नवप्रदेश। सुमन कुमार ने इंडियनऑयल के बोर्ड में निदेशक (योजना और व्यापार विकास) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इस पदभार से पहले, वह कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में अन्वेषण एवं उत्पादन क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे।



सुमन कुमार एक अनुभवी पेशेवर हैं, जिनके पास 30 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उन्होंने प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसायों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने एमआईटी मुजफ्फरपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है

और एमबीए के साथ-साथ उन्नत प्रबंधन प्रशिक्षण भी लिया है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने एलपीजी संचालन,

पेट्रोलियम उत्पाद बिक्री, ऊर्जा संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं।

अपने नए पद पर, कुमार इंडियनऑयल के विस्तारित व्यापार पोर्टफोलियो

का नेतृत्व करेंगे, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, प्राकृतिक गैस, अन्वेषण एवं उत्पादन, हरित पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस वितरण और विस्फोटक शामिल हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता इंडियनऑयल की रणनीतिक वृद्धि को ऊर्जा क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में नई दिशा प्रदान करेंगी।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने लॉन्च की OBD2B कंप्लायंट हॉर्नेट 2.0

रायपुर/नवप्रदेश। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने आज अपडेटेड OBD2B कंप्लायंट हॉर्नेट 2.0 को लॉन्च किया, जो आधुनिक स्टायलिंग,

नवीनतम तकनीक और बेहतर सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है। नई 2025 होंडा हॉर्नेट 2.0 की कीमत ₹. 1,56,953 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है और यह अब पूरे भारत में HMSI रेड विंग और बिगविंग डीलरशिप पर उपलब्ध है। अपडेटेड हॉर्नेट 2.0 को पेश करते हुए, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और सीईओ, श्री त्सुत्सुमु ओटानी ने कहा, “अगस्त 2020 में पहली बार पेश किए जाने के बाद से ही हॉर्नेट 2.0 इस सेगमेंट में



गेम-चेंजर रही है। वर्षों से, हमने इस मोटरसाइकिल को लगातार अपडेट किया है और स्पेशल MotoGP एडिशन मॉडल भी लॉन्च किए, जिन्हें हमारे ग्राहकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। नई

“इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के निदेशक, सेल्स और मार्केटिंग, श्री योगेश माथुर ने कहा, “हम हॉर्नेट 2.0 के नवीनतम संस्करण को पेश करते हुए बेहद उत्साहित हैं, जो नए और रोमांचक फीचर्स के साथ आता है। इस मोटरसाइकिल में अब अधिक आक्रामक ग्राफिक्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक उन्नत डिजिटल TFT डिस्प्ले, और होंडा सेलेक्टबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC) और डुअल-चैनल ABS जैसी सुरक्षा सुविधाएँ हैं। प्रदर्शन प्रेमियों के लिए डिज़ाइन की गई यह बाइक, स्ट्रीटफाइटर अनुभव को नए आयाम पर ले जाने के लिए तैयार है।

खेल

क्रिकेट जगत ने इंग्लैंड पर शानदार जीत के लिए अफगानिस्तान को सराहा

मुंबई। क्रिकेट जगत ने अफगानिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम, खासकर इब्राहिम जादरान और अजमतुल्लाह उमरज़ई की जमकर प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने बुधवार को लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पूर्व चैंपियन इंग्लैंड पर शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले पावर-प्ले में 37/3 पर सिमरटने के बाद, अफगानिस्तान ने जादरान के शानदार 177 रन की मदद से चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी (40), मोहम्मद नबी (40) और उमरज़ई (41) के महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत 325/7 का विशाल स्कोर बनाया। उमरज़ई ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, उन्होंने 5-58 विकेट लिए, जो किसी अफगान गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है, जबकि इंग्लैंड की टीम जो रूट के 120 रनों के बावजूद 317 रनों पर आउट हो गई। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने

एक्स (पूर्व में टिवटर) पर एक पोस्ट में लिखा, अफगानिस्तान की ओर से शानदार प्रदर्शन..जीत का पूरा हकदार...इंग्लैंड ने पिछले कुछ सालों से व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इन परिस्थितियों में यह परिणाम आश्चर्यजनक नहीं है।अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने उमरज़ई के प्रदर्शन की सराहना करते हुए इसे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड प्रदर्शन बताया।एसीबी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर एक्स पर कहा, शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन- और यह अजमत ओमरज़ई के लिए एक और विशेष ऑलराउंड प्रदर्शन था, जिन्होंने अपना पहला पांच विकेट लिया और इंग्लैंड पर अफगानिस्तान की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।पूर्व भारतीय कप्तान और जाने-माने कमेंटेटर रवि शास्त्री ने भी बुधवार को अफगानिस्तान टीम के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की और इंग्लैंड को उपमहाद्वीप में खेलने को गंभीरता से



लेने की सलाह दी। शास्त्री ने कहा, अफगानिस्तान। आप लोग कमाल करते हैं। कमाल कर रहा। इंग्लैंड के लिए। उपमहाद्वीप में खेलने को बिना किसी बहाने के गंभीरता से लें। तभी आपको एक ऐसी टीम के रूप में पहचाना जाएगा जो यात्रा कर सकती है।लाहौर के गढ़ाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा जश्न मनाने के कुछ अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिले। बुधवार की जीत कई लोगों को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 2023 वनडे विश्व कप में इंग्लैंड पर अफगानिस्तान की इसी तरह की उलटफेर भरी जीत की याद दिलाएगी।अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी उनके प्रदर्शन से

उत्साहित थे और उन्होंने कहा कि पूरा देश इस जीत से खुश होगा। उन्होंने कहा, एक टीम के रूप में, हम खुश हैं और मुझे यकीन है कि पूरा देश इस जीत से खुश होगा। पहली बार हमने उन्हें 2023 विश्व कप में हराया। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हम एक टीम के रूप में दिन-प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हैं, और यही हमने पिछले कुछ विश्व कप में दिखाया है। आज, यह एक तनावपूर्ण मैच था, लेकिन हमने इसे वास्तव में अच्छी तरह से नियंत्रित किया। मैं परिणाम से खुश हूं।अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा, हमारी टीम की खूबसूरती यह है कि हमारे पास प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी हैं, और साथ ही, हमारे पास वरिष्ठ खिलाड़ी भी हैं जो शीर्ष स्तर पर हैं। हर कोई अपनी भूमिका जानता है और इस टीम में उन्हें क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले मैच के लिए इस गति को अपने साथ ले जाएंगे।

आईसीसी मैच रेफरी डेविड बून क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड में शामिल होंगे

मेलबर्न। पूर्व टेस्ट बल्लेबाज डेविड बून को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) बोर्ड में नियुक्त किया गया है। वे पॉल ग्रीन द्वारा खाली किए गए पद को भरेंगे, जिन्होंने क्रिकेट तस्मानिया के प्रतिनिधि के रूप में छह साल बाद पद छोड़ दिया था।

बून, जो वर्तमान में आईसीसी मैच रेफरी हैं, 28 मार्च को सीए बोर्ड में शामिल होने के लिए पाकिस्तान और दुबई में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईसीसी के साथ अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक, बून ने 107 टेस्ट मैच खेले और 43.65 की औसत से 7,422 रन बनाए, जिसमें 21 शतक (ऑस्ट्रेलिया के एक अन्य महान खिलाड़ी - नील हार्वे के समान ही टेस्ट शतक) और 99 कैच शामिल हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पांचवें सबसे अधिक रन बनाने वाले और पांचवें सबसे अधिक कैच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे। 1984/85 और 1995/96 के बीच 107 टेस्ट मैच खेलने के



कारण वे एलन बॉर्डर के बाद 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने गए। 181 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 37.04 की औसत से 5,964 रन बनाए, जिसमें पांच शतक शामिल हैं। वे 1987 की आईसीसी विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे, जिन्होंने फाइनल में 75 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का सम्मान प्राप्त किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सात रनों से हराया। बून, जो 2014 से क्रिकेट तस्मानिया के निदेशक और 2022 से अध्यक्ष हैं, क्रिकेट तस्मानिया के महाप्रबंधक रहे हैं और 2000 से 2011 तक ऑस्ट्रेलियाई चयन पैनल के सदस्य थे। वे 2011 में आईसीसी मैच रेफरी बने, एक भूमिका जिसे वे छोड़

संस्थानों में टैबलेट की मांग में पिछले वर्ष की तुलना में 104.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि थी। सरकार द्वारा फंडेड शिक्षा परियोजनाओं ने इस वृद्धि को बढ़ावा दिया, जबकि वेरी लार्ज बिजनेस (वीएलबी) सेगमेंट में पिछले वर्ष की तुलना में 9.9 प्रतिशत की गिरावट आई। आईडीसी इंडिया और दक्षिण एशिया के शोध विश्लेषक प्रियांश तिवारी ने कहा, “इंग्लैंड टैबलेट में बेहतर कैमरे, सॉफ्टवेयर अपडेट और ऐप इंटीग्रेशन के साथ, टैबलेट कम प्रोडक्टिविटी और मॉनोरंजन के लिए पसंदीदा डिवाइस बन रहे हैं और पोसी डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर की वजह से कंज्यूमर सेगमेंट मजबूत रहा और इस सेगमेंट में सालाना आधार पर 19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 60 प्रतिशत से अधिक शिपमेंट एट्री-लेवल टैबलेट के होने के बावजूद, कंज्यूमर सेगमेंट में एक्वेज सेलिंग ग्राइस (एएसपी) वित्त वर्ष 2023 में 309 डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 336 डॉलर हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कमर्शियल सेगमेंट ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 69.7 प्रतिशत बढ़ा, जिसका मुख्य कारण शैक्षणिक



